आईआईएम रांची करेगा स्कूल विलय की जांच

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के 5800 प्रारंभिक स्कूलों के विलय (पुनर्गठन) का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराने का निर्णय लिया है। स्कूलों के विलय और 7001 शिक्षकों के हुए रेशनलाइजेशन की जांच की जिम्मेदारी आईआईएम, रांची को दी जायेगी। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है और कैबिनेट मंजूरी का इंतजार है।

राज्य सरकार आईआईएम बंगलुरू से स्कूलों के विलय और शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया की जांच करना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। आईआईएम रांची ने इस मामले पर जांच की इच्छा जतायी थी, इसके बाद राज्य सरकार उन्हें थर्ड पार्टी वेरिफिरेकशन की जिम्मेदारी देने जा रही है। आईआईएम रांची किस आधार पर जांच करेगी और इसके क्या-क्या आधार होंगे इसका गाइडलाइन अभी तैयार नहीं हुआ है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का गाइडलाइन तैयार किया जायेगा।

शिक्षक-छात्र का अनुपात गड़बड़ : प्राथमिक स्कूलों में पहली से पांचवीं में 30 छात्र-छात्राओं पर एक शिक्षक और मध्य विद्यालयों में छठी से आठवीं में 35 छात्र-छात्राओं पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात सही नहीं है। कहीं छात्र की तुलना में शिक्षक अधिक हैं तो कहीं शिक्षक कम हैं। स्कूलों के विलय और शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की वजह से करीब 4800 शिक्षकों की रिक्तियां खत्म होने का विभाग का दावा है।

शिक्षा विभाग ने पिछले साल दो चरणों में 1200 और 4600 स्कूलों का विलय किया था। स्कूलों के विलय और शिक्षकों के रेशनलाइजेशन पर कई सवाल उठे थे। शिक्षा विभाग शिक्षक-छात्र का अनुपात ठीक कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा कर रहा है। इस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाने की योजना थी। इस बीच सांसद और विधायकों से लेकर शिक्षक संघ व अन्य संगठनों ने विलय और रेशनलाइजेशन पर आपत्ति जताई।

आईआईएम रांची को 43 लाख देगी सरकार

शिक्षा विभाग ने आईआईएम रांची से जांच कराने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। विभाग आईआईएम को मनोनयन के आधार पर काम की जिम्मेदारी देना चाहती है। इसके एवज में 43 लाख रुपये भुगतान किए जाएंगे। विभाग ने इस प्रस्ताव पर कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेज दिया है। कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।

> स्कूलों के पुनर्गठन और शिक्षकों रेशनलाइजेशन का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद आईआईएम रांची को जांच की जिम्मेदारी दी जाएगी।
>
> -एपी सिंह, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग

फैक्ट फाइल

- राज्य में कुल स्कूल- **35** हजार
- नियमित शिक्षक -**56** हजार
- पारा शिक्षक- **65** हजार
- कुल बच्चे- **34** लाख
- स्कूलों का विलय: **5800**

Hindustan, 23.05.2019, Pg. 04